

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर 17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 नवम्बर 2003—कार्तिक 23, शक 1925

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2003

क्रमांक ई-1-5/2003/1/2.—श्री एल. एन. सूर्यवंशी, भा.प्र.से. (1992), कलेक्टर, जिला बस्तर को तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री बी. एस. अनन्त, भा.प्र.से. (1993), कलेक्टर, जिला जशपुर को तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2003

क्रमांक 6887A/4513/21-ब (छ. ग.) 2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्वारा श्री बी. एल. साहू, अधिवक्ता, जगदलपुर को दिनांक 31-3-2004 तक की परिवीक्षा अवधि के लिये कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा सत्र खण्ड के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2003

क्रमांक 6911/1808/21-ब (छ. ग.) 2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्री एल. एन. नाग, संयुक्त कलेक्टर, धमतरी को धमतरी जिले में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नियुक्त करता है, और यह निर्देश देता है कि वे उक्त संहिता के अधीन तथा तत्समय प्रदत्त किसी अन्य विधि के अधीन जिला दण्डाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2003

क्रमांक 6992/डी-4294/21-ब (छ. ग.)/03.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी/4997/21-ब/छ.ग./2003, दिनांक 1-8-2003 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 9 सन् 1982) के अध्याय तीन की धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये/राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि समिति निम्नानुसार सदस्यों को नामांकित करती है :-

ब-मनोनीत सदस्य

11. अधिवक्ता परिषद् द्वारा नामांकित सदस्य :-

1. श्री शैलेन्द्र दुबे, अधिवक्ता, तारबहार, बिलासपुर
2. श्री रामनारायण व्यास, अधिवक्ता, विवेकानंद नगर, रायपुर

12. राज्य शासन द्वारा नामांकित सदस्य :-

1. श्री चरण दास महंत, सांसद
2. श्री गणेश शंकर बाजपेयी, विधायक

Raipur, the 30th October 2003

No. 6992/D-4294/XXI-B/C.G./03.—In exercise of the powers conferred by Chapter III Section 4 of the Chhattisgarh Adhivakta Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 9 of 1982) in sequence of this Department Notification No. 4997/1609/21-B/C.G./03, dated 1-8-2003. The State Government hereby nominates the following persons in the Chhattisgarh Advocate Welfare Fund Committee for the purpose of this Act :-

NOMINATED MEMBERS

11. Nominated by the Bar Council

1. Shri Shailendra Dubey - Advocate, Tarbahar Bilaspur.
2. Shri Ramnarayan Vyas - Advocate, Vivekanand Nagar, Raipur

12. Nominated by the State Government

1. Shri Charan Das Mahant - Member of Parliament.
2. Shri Ganesh Shankar Bajpai. - Member of Legislative Assembly.

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2003

क्रमांक 7004/डी-4522/छ.ग./03/21-ब.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री अब्दुल हफीज कुरेशी, अधिवक्ता रायपुर को फास्ट ट्रेक कोर्ट, रायपुर में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 29-2-2004 तक के लिये अथवा फास्ट ट्रेक कोर्ट की समाप्ति तक जो भी अवधि पहले आये, राज्य शासन की ओर से पैरवी करने हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है। किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2003

क्रमांक 4934/1345/आजाक/2003.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी में अकादमी की पंजीकृत संविधान की धारा 7 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 6 में की गई व्यवस्था के अनुरूप निम्नानुसार पदाधिकारियों को मनोनीत करता है :—

क्रमांक (1)	नाम (2)	पद (3)
1.	श्री अमीर अली अमीर	अध्यक्ष
2.	सुश्री उजमा अख्तर	उपाध्यक्ष
3.	श्री सेमुअल डेनियल शॉक उर्फ शौक जालन्धरी.	उपाध्यक्ष
4.	श्री रजा हैदरी	सदस्य
5.	श्री रउफ परवेज	सदस्य
6.	श्री जफर रउफी	सदस्य
7.	श्री काविश हैदरी	सदस्य
8.	श्री सईद खान	सदस्य
9.	श्री रौनक जमाल	सदस्य
10.	श्री मोहसिन अली सुहैल	सदस्य

2. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के चीफ पेट्रन तथा भारसाधक मंत्री एवं राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग अकादमी के पेट्रन होंगे.

3. अकादमी के उक्त वर्णित सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा.

Raipur, the 1st October 2003

No. 4934/1345/TDD/25-1/2003.—In exercise of powers conferred vide section 7 and in accordance with provision contained in section 6 of the registered constitution of Chhattisgarh Urdu Academy, the State Government hereby nominates following members in the said academy :—

Sl. No. (1)	Name (2)	Post (3)
1.	Shri Ameer Ali Ameer	Chairperson

(1)	(2)	(3)
2.	Ms. Ujma Akhtar	Vice-Chairperson
3.	Shri Samuel Daniel Shauq alias Shauq Jalandhari.	Vice-Chairperson
4.	Shri Raza Hyderi	Member
5.	Shri Rauf Parvez	Member
6.	Shri Zafar Raufi	Member
7.	Shri Kawish Hyderi	Member
8.	Shri Sayeed Khan	Member
9.	Shri Rounak Zamal	Member
10.	Shri Mohsin Ali Suhail	Member

2. Chief Minister, Govt. of Chhattisgarh, shall be the Chief Patron and Minister as well as State Minister-in-charge of the Department of ST and SC Development shall be the patrons.

3. Tenure of the aforesaid members of the Academy shall be three years. *

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरजियस मिन्ज, प्रमुख सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2003

क्रमांक एफ/11-11/2003/16.—चूंकि उपमहाप्रबंधक आई. बी. पी. कम्पनी लिमि. गोपालपुर कटघोरा, जिला कोरबा के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व जनरल सेक्रेटरी केमिकल्स एम्पलाईज यूनियन मजदूर सभा भवन नन्दिनी रोड, भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक उपमहाप्रबंधक आई.बी.पी. कम्पनी गोपालपुर कटघोरा, जिला कोरबा के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किए जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतः छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

1. क्या, बी.जी.सी. (बिजनेस ग्रुप केमिकल) को कम्पनी से अलग करने की योजना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां, तो इसका क्या स्वरूप होना चाहिए ?
2. क्या प्रबंधतंत्र का एल. डी. (लार्ज डिमेटर) बारूद का प्रमुख उत्पादन को रोका जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां, तो इसकी क्या योजना होनी चाहिए ?
3. क्या प्रबंधतंत्र का केमिकल डिवीजन ल्यूब के विपणन पर रोक लगाया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां, तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
4. क्या प्रबंधतंत्र का केमिकल डिवीजन को बंद या पृथक् करने की कोशिश किए जाने से सेवा नियुक्तों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ? यदि हां तो इस व्यवस्था का क्या स्वरूप होना चाहिए ?

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2003

क्रमांक एफ 11-11/03/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि कोरबा के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसिलियेटर) को निर्दिष्ट जनरल सेक्रेटरी केमिकल्स एम्पलाईज यूनियन मजदूर सभा भवन नन्दिनी रोड भिलाई एवं उपमहाप्रबंधक आई.बी.पी. कम्पनी लिमि. गोपालपुर, कटघोरा, जिला कोरबा के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विवाद के संबंध में समझौता नहीं हो सका.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 3/म. प्र. आई. आर./2000

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2003

क्रमांक एफ 11-7/2003/16.—छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (1958 का क्रमांक 25) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा निर्देशित करता है कि इसके पूर्व दिए गए आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए आगामी आदेश तक लोक हित को दृष्टिगत करते हुए अनुसूची के स्तंभ 1 में दर्शाए गए स्थापना को अत्यावश्यक सेवा मानकर इस अधिनियम की धारा जो स्तंभ क्र. 2 में दर्शाया गया है, स्तंभ 3 में निर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे.

अनुसूची

संस्थानों का वर्ग (1)	अधिनियम की धारा (2)	शर्तें (3)
लिक्विड पेट्रोलियम धारा 13 (1) एवं (3) प्रत्येक सेवायुक्त गैस की वितरण को सवैतनिक संस्थानों (मिट्टी सेवा साप्ताहिक तेल वितरण अवकाश देना संस्थानों इसमें होगा. सम्मिलित नहीं होंगे)		

यह अधिसूचना उस तिथि से प्रभावशील होगी जिस तिथि को यह राजपत्र में प्रकाशित होगी एवं यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. मूर्ति, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 18 सितम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 148/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बड़ेदेवगांव	3.544	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्रमांक-4, डभरा.	टर्न की पद्धति से कुरदा वितरक नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 23 अक्टूबर 2003

प्र. क्र./1 अ-82/वर्ष 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	कवर्धा	0.23	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि., कवर्धा.	कवर्धा बायपास मार्ग निर्माण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, दिनांक 1 अगस्त 2003

क्रमांक 4961/भू-अर्जन/02/अ-82/2002-03. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
(ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम-कुम्हाररास, प.ह.नं. 15
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.639 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
184/5	0.040
184/2 ख	0.729
184/23 घ	0.486
184/23 ग	0.364
184/23 क	0.202
184/22	0.182
173, 174, 180, 190, 191/1	0.040
173, 174, 180, 190, 191/2	0.048
173, 174, 180, 190, 191/3	0.270
175	0.061
172	0.081
168, 169, 179	0.299
166	0.024
184/27 क	0.162
184/24	0.550
184/1 छ	0.162

(1)	(2)
184/1 ख	0.210
129	0.081
184/1 ज	0.121
133/2	0.526
योग	4.639

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कुम्हार-
रास जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर एवं भू-अर्जन
अधिकारी, दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 30 अक्टूबर 2003

क्र. 1579/अ-82/सन् 03. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-गुण्डरदेही
(ग) नगर/ग्राम-मोहदीपाट, प. ह. नं. 02
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.90 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
209/1	0.30

(1) (2)

अनुसूची

209/3	0.05
209/4	0.30
205	0.05
208	0.22
202/1	0.15
202/2	0.05
212/2	0.15
204	0.35
206	0.30
197/1	0.30
197/2	0.35
197/3	0.22
198	0.06
188/3	0.22
192/2	0.18
189/4	0.30
189/5	0.05
189/7	0.10
161/6	0.60
161/2	0.05
161/5	0.15
189/8	0.40

योग 23 4.90

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-बघेली, प. ह. नं. 02

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.96 एकड़

खसरा नम्बर

रकबा
(एकड़ में)

(1)

(2)

736/10	0.25
674	0.10
676	0.12
65/13	0.25
382/4	0.20
382/15	0.06
690/1	0.55
690/4	0.45
690/5	0.80
272	0.02
230/4	0.20
382/7	0.50
690/3	0.24
678/1	0.35
681	0.22
382/14	0.01
682	0.38
686	0.10
687	0.05
688	0.40
204	0.15
203	0.02
689	0.10
310	0.04
382/2	0.20
690/2	0.08
382/5	0.28
309	0.20
308	0.20
291	0.05
292	0.05
293	0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), पाटन मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 अक्टूबर 2003

क्र. 1581/अ-82/सन् 03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

(1) (2) अनुसूची

294	0.05
295	0.15
296	0.05
299	0.01
283	0.15
284	0.06
270	0.12
271	0.12
268	0.01
267	0.04
266	0.06
265	0.06
169	1.20
256	0.08
255	0.04
230/4	0.05
230/6	0.20
230/5	0.30
168	0.15
166	0.02
65/1	0.22
65/2	0.22
177	0.80
178	0.22
60	0.01
59	0.30
735	0.60

योग 59 11.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 अक्टूबर 2003

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-गुण्डरदेही

(ग) नगर/ग्राम-माहुद, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.03 एकड़

खसरा नम्बर

रकबा
(एकड़ में)

(1)

(2)

1288/1	0.60
959	0.30
1275	0.45
1270	0.35
1269	0.70
961	0.10
960	0.28
958	0.30
957	0.70
956	0.15
946	0.40
945	0.45
941	0.30
911	1.00
914	0.20
907	0.40
887	0.45
888	0.20
886/2	0.30
885/1	0.40
884	0.40
883	0.60

योग 22 9.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1577/अ-82/सन् 03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

दुर्ग, दिनांक 30 अक्टूबर 2003

अनुसूची

क्र. 1578/अ-82/सन् 03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-गुण्डरदेही
(ग) नगर/ग्राम-मटेवा, प. ह. नं. 05
(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.71 एकड़

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-गुण्डरदेही
(ग) नगर/ग्राम-गब्दी, प. ह. नं. 06
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.55 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
473	0.08
472	0.20
470	0.20
469	0.08
468	0.08
447/1	0.10
446	0.15
445	0.13
444	0.08
440	0.45
योग	1.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 अक्टूबर 2003

क्र. 1580/अ-82/सन् 03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
75	0.95
66	0.05
351	0.16
64	0.35
130	0.30
149	0.70
65	0.06
59/2	0.22
638/6	0.12
638/1	0.01
58	0.20
54	0.30
50/7	0.20
50/5	0.05
55	0.08
114/3	0.22
115	0.20
114/1	0.02
114/2	0.12
113	0.12
117	0.02
132	0.01
611	0.15
131/2	0.10
140	0.28
137	0.12
150	0.12
330	0.15
349	0.18
747	0.20
350	0.02
748	0.15
352	0.05

(1) (2)

337	0.12
339	0.10
338	0.12
331	0.06
752	0.02
753	0.22
754/2	0.10
754/3	0.25
603	0.20
626	0.15
631	0.02
755/1	0.15
759	0.10
581	0.25
594	0.15
586	0.10
604	0.02
585	0.12
595	0.12
596	0.20
606	0.30
600	0.02
605	0.12
602	0.05
612	0.18
621	0.15
623	0.01
627	0.08
625	0.13
632	0.20
634	0.12
638/7	0.15
638/5	0.10
638/3	0.20
638/2	0.25
185	0.10

योग 68 10.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 31 जुलाई 2003

रा. प्र. क्र. 04/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-सामरी (कुसमी)
(ग) नगर/ग्राम-करमी उरौव टोली,
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.383 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
513/2	0.049
517	0.032
513/5	0.081
458	0.073
515	0.283
552	0.162
512/2	0.101
509/2	0.065
553	0.243
551	0.081
512/1	0.101
461/2	0.113

योग 12 1.383

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-डीपाडीहकला कोठली मार्ग पर गलफुल्ला सेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 जुलाई 2003

अनुसूची

रा. प्र. क्र. 05/अ-82/99-2000.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-कुसभी
(ग) नगर/ग्राम-डीपाडीहकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.266 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
904	0.025
902	0.077
899	0.101
903	0.024
900	0.040
योग	5 0.266

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-डीपाडीहकला कोठली मार्ग पर गलफुल्ल सेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 जुलाई 2003

रा. प्र. क्र. 06/अ-82/99-2000.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-पाल
(ग) नगर/ग्राम-रामपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.720 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5	0.340
26	0.040
11	0.030
29	0.030
10	0.280
योग	5 0.720

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रामानुजगंज-वाइफ नगर सेन्दूर सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 जुलाई 2003

रा. प्र. क्र. 09/अ-82/99-2000.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-पाल
(ग) नगर/ग्राम-पचावल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.744 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(1)	(2)
157	0.121	118/3	0.129
1118	0.023	159/2	0.008
159	0.178	157	0.113
262/2	0.340	159/3	0.049
156	0.302	194	0.081
		195	0.040
योग	5	193/5, 158	0.016
	0.744	217/7	0.024
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सनावल		217/8	0.053
पचावल मार्ग पर पागम सेतु पहुंच मार्ग निर्माण.		196/1	0.053
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया		196/2	0.040
जा सकता है.		198/1	0.344
		219/1	0.364
		196/3	0.045
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,		217/5	0.049
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.		219/6, 7	0.053
		218/2	0.117
		218/3	0.279
		218/4, 5, 10, 11	0.121
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं		239/1	0.040
पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन		239/2	0.061
राजस्व विभाग		238	0.028
		240	0.016
		242	0.109
रायगढ़, दिनांक 29 सितम्बर 2003		237	0.020
		236	0.073
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 116/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य		235/1	0.020
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के		266/2	0.020
पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक		267	0.036
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894		268	0.040
(क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया		269	0.089
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		282/1	0.012
		282/6	0.024
		282/2	0.129
		282/5	0.028
		283/7	0.061
		282/8	0.016
		283/1	0.105
		283/3	0.065
		378/6	0.227
		381/1	0.036

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-घघरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.490 हेक्टेयर

(1)

(2)

अनुसूची

381/2	0.049
378/3	0.081
121/1	0.077
118/7	0.081
114/1, 115/1, 116/1	0.040
116/2	0.121
121/2	0.085
121/5	0.028
121/3	0.045
218/6	0.028
218/3	0.028
229	0.154
228	0.016
227/1	0.040
38/2	0.231
226/1	0.008
37/1	0.004
37/3, 4	0.142
2/1, 2/2, 3/1 17	0.142
2/1, 2/2, 3/1 11	0.203
2/1, 2/2, 3/1 9	0.073
2/1, 2/2, 3/1 8	0.008
2/1, 2/2, 3/1 12	0.203
2/1, 2/2, 3/1 14	0.020
2/1, 2/2, 3/1 5	0.203
2/1, 2/2, 3/1 13	0.057
2/1, 2/2, 3/1 10	0.049

योग	64	5.490
-----	----	-------

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से कुरदा शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 सितम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 119/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-खरसिया
(ग) नगर/ग्राम-हालाहुली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.479 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

146/2	0.198
145	0.012
149/2	0.243
150, 151 1	0.032
150, 151 2	0.122
150, 151 3	0.045
166/2	0.004
166/3	0.089
166/1	0.073
170/2	0.008
169	0.016
172/2	0.093
172/1	0.130
171/2	0.012
174	0.004
173	0.049
176/2	0.113
175/1	0.012
176/1 क	0.053
178	0.085
179	0.004
88/1	0.028
88/2	0.061
88/4	0.040
88/7	0.081
87	0.162
81	0.203
86/2	0.061
80/3	0.077
199/2	0.028
200/2	0.049
201/2	0.085
200/1	0.016

(1)	(2)	(1)	(2)
201/1	0.057	117/2	0.077
201/3	0.065	22/4	0.040
202/1	0.008	29/21	0.089
131/1	0.061	29/2	0.093
योग	37	116/5	0.020
	2.479	22/3	0.032
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से कुरदा शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.		116/6	0.016
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.		21/3	0.020
		21/2	0.020
		17/1	0.182
		123/1	0.061
		123/2	0.061
		17/3	0.061
		14/2	0.045
		14/1	0.097
		14/5	0.101
		13/1	0.101
		12/1	0.061
		12/3	0.036
		10/8	0.065
		10/4	0.053
		29/22	0.049
		29/24	0.065
		29/13	0.113
		29/8, 9	0.004
		47/1	0.364
		45	0.073
		117/1	0.049
		116/8	0.036
		123/3	0.069
		114/2	0.125
		147/2	0.587
		111/1	0.170
		111/3	0.125
		110/2	0.008
		111/4	0.028
		111/2	0.049
		110/3	0.117
		109/3	0.097
		108/2	0.024
		109/5	0.012
		27/3	0.069
		27/5	0.016

रायगढ़, दिनांक 29 सितम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 137/अ-82/2002-2003. —चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-खरसिया
(ग) नगर/ग्राम-पुरेना
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.250 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
27/4	0.186
27/7	0.073
27/6	0.101
27/2	0.036
26/2	0.142
114/3	0.146
26/3	0.101
114/5	0.146
26/1	0.105
19/1	0.364

(1)	(2)
27/4	0.016
26/3	0.109
25/10	0.028
25/15	0.004
25/11	0.036
25/12	0.077
योग	59
	5.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से कुरदा शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 नवम्बर 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-घरघोडा

(ग) नगर/ग्राम-तुमोडीह एवं पंजीपथरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-तमीडीह-131.932 हेक्टेयर

पूँजीपथरा-95.118 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रक्तबा
(हैक्टोयर में)

(1)

(2)

तूषीडोह

305/1	1.506
336	1.092
384	1.019
367	1.918

(1)	(2)
291	0.761
389	1.084
408	5.937
292	0.328
298	0.441
295	1.424
300/1	5.196
296	0.833
320	0.433
374	0.567
318	0.502
335	2.736
340	0.376
402	3.493
401	1.129
406	3.840
332	0.983
379	0.785
398	0.579
396	0.789
304	0.644
309	3.169
313	1.777
337	2.654
310	3.157
315	4.957
339	1.019
369	0.829
372	0.223
390	2.020
303	0.607
322	0.652
333/1	0.515
365/3	0.049
400/1	0.372
400/8	0.324
314/5	0.138
314/7	0.324
314/8	0.527
400/3	0.243
400/6	0.146
338/1	0.802

(1)	(2)	(1)	(2)
312	11.683	400/2	0.372
370/1	0.613	386/1	0.688
399/1	1.087	366/2	0.202
314/1	0.380	282	0.470
314/4	0.231	307	2.890
376/4	0.121	314/6	0.049
407/3	0.749	385	0.729
342/3	0.121	400/5	2.181
366/1	0.405	409/1	1.238
404	0.072	400/4	0.283
407/9	0.162	407	0.178
391/1	2.905	381	2.327
397	2.759	393	0.425
386/2	0.181	317	1.627
407/4	0.749		
407/7	0.384	योग	105 130.657
410/2	0.405		
338/3	0.162		पूँजीपथरा
376/2	0.283		
333/2	0.500	187	0.750
334	1.197	189	0.280
370/2	0.613	212/1	0.688
399/2	1.187	192/1	0.230
370/3	0.612	190	0.430
331/1	0.141	191	3.040
367/2	0.085	195/9	0.030
378	2.246	195/10	0.930
380	1.582	195/14	0.140
301/1	1.424	195/17	0.405
302/1	0.518	195/1	0.303
294	0.470	215	1.840
392	5.368	216/4	0.607
399/3	1.187	195/16	0.100
377	3.213	195/19	0.133
290	0.101	195/3	0.303
371	0.498	195/4	0.280
373	0.510	195/12	0.930
400/9	0.304	195/15	0.200
365/4	0.057	195/18	0.101
395	0.721	216/3	0.405
289	0.194	216/8	1.213
316	3.950	195/5	0.080
314/9	0.787	195/6	0.930

(1)	(2)	(1)	(2)
195/8	0.080	172/21	0.607
195/13	0.930	172/25	0.464
218	0.840	212/2	0.910
220/1	1.000	216/2	1.309
220/3	0.702	212/4	1.040
220/5	1.000	208	1.790
221/2	0.498	195/2	0.303
220/2	1.257	195/7	0.101
220/4	0.405	195/11	0.930
221/1	0.405	216/1	0.405
221/3	0.933	211	0.980
222	2.080	193	0.200
234	5.950	216/7	2.024
224	2.020	206	0.470
172/10	0.987	209	0.500
172/4	2.174	210	0.820
172/27	0.721	172/1	0.502
172/30	3.000	216/5	0.608
172/2	0.502	165	0.870
172/5	0.607	172/8	0.987
172/7	0.987	166	1.770
172/9	0.987	172/12	2.174
172/20	0.202	172/13	2.205
172/29	0.500	172/24	0.607
172/30	0.500	172/26	0.407
172/3	0.503	172/28	0.881
172/6	1.959	163	0.790
216/6	1.252	192/2	0.230
172/14	0.987	212/3	1.327
172/15	0.987		
172/16	1.000		
172/17	1.000		
172/18	0.607		
172/28	1.000		
172/23	0.561		
172/32	0.549		
172/11	0.890		
225	2.020		
226	2.020		
239	0.820		
195/20	0.200		
172/22	0.607		
172/19	1.000		

योग 88.082

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-औद्योगिक परिक्षेत्र हेतु भूमि अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

